मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

भीड़तन्त्र द्वारा ब्लैकमेल करने की बढती प्रवृत्ति ढींगड़ा भाईयों से पैसा ऐंठने वारिस उतरे सड़कों पर 3

मोदी और केजरीवाल–एक ही सिक्के के दो पहलू 5

– जलवायु परिवर्तन को लेकर स्वार्थ प्रेरित उलझाव।
– मोदी और यशोदाबेन 6

तीन करोड़ मुकदमों तले दबी न्यायपालिका को सशक्त और परफ़ेक्ट बनाने की जरूरत : मोदी 8

वर्ष 28 अंक 11 फरीदाबाद, वीरवार, 16-30 अप्रैल 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

पर्यावरण व्यापार, प्रदूषण अपार, कहे स्वतंत्र कुमार

दिल्लीवासी मोहम्मद तुगलक को इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (दक्षिण भारत) ले जाने के समय हर दिल्लीवासी को भी वहां जाने का फ़र्मान जारी किया था। कहते हैं बमुश्किल मरते-गिरते चन्द लोग ही दौलताबाद पहुंच सके थे। ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज स्वतंत्र कुमार ने दिल्लीवासियों के दिलो-दिमाग़ में मोहम्मद तुगलक को फ़िर से जिंदा कर दिया है। दस वर्ष से अधिक के डीज़ल वाहनों की जब्ती का फ़र्मान देकर उन्होंने प्रशासन एवं जनता में खलबली मचा दी है। न इस ट्रिब्यूनल को ऐसे आदेश देने का हक है और न ही यह आदेश किसी वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। सवाल है 10 वर्ष की सीमा ही क्यों? न्याय का तकाज़ा था कि हर प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देकर उसका पक्ष भी सुना जाता। आख़िर स्वतंत्र कुमार इतने उतावले क्यों हैं? कहने वाले क्यों न कहें कि वाहन निर्माताओं से सांठ-गांठ एक बड़ा कारण है।

मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद ब्यूरो

स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल ने गत सप्ताह घोषित किया कि वे शहर में प्रदूषण नापने के लिये घड़ीनुमा एक यंत्र लगवायेंगे। इसमें तालियां बजाने जैसी कोई बात नहीं है। यह यन्त्र प्रदूषण दूर करने या घटाने जैसा कोई काम नहीं करेगा, बल्कि पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बतायेगा। यह मात्रा जान कर आम आदमी सिवाय चिन्तित होने अथवा प्रदूषण बढवाने वाली व्यवस्था को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पायेगा।

संदर्भवश यह जान लेना जरूरी है कि तमाम तरह के प्रदूषण (वायु, जल तथा ध्वनि)आदि के लिये सरकारी भ्रष्टाचार तथा पूंजीपतियों की अंधा मुनाफ़ा कमाने की हवस जिम्मेवार है। हरियाणा सहित लगभग तमाम राज्यों में बने पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड लूट के पर्याय बन कर रह गये हैं। सरकार चाहे किसी की रही हो इस बोर्ड के चेयरमैन का पद सदैव करोड़ों में बिकता रहा है। चेयरमैन फ़िर आगे ज़िलेनुसार अधिकारियों के पद बेचते आ रहे हैं। इनका काम प्रदूषण नियन्त्रण न होकर केवल प्रदूषण फ़ैलाने के एवज में ड्राफ्ट द्वारा सरकारी फ़ीस तथा टेबल के नीचे से अपनी 'फ़ीस' वसूलना है। इस तरह की वसूली में कई अधिकारी रंगे हाथों पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन फ़िर भी काम ज्यों का त्यों जारी है।

राज्य भर के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल एवं बायोवेस्ट का करोड़ों का ठेका सरकार अपने किसी चहेते को दिला देती है, जो तमाम छोटे-बड़े, सरकारी व गैरसरकारी अस्पतालों, यहां तक कि घरों में छोटा-मोटा क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों तक से भी वसूली करता है परन्तु बायोवेस्ट का विधिवत निस्तारण करने की बजाय उसे दांय बांय कर देता है। इस बाबत 'मज़दूर मोर्चा' में कई बार विस्तृत रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। और तो और बायोवेस्ट को इधर-उधर फेंकते हुए ठेकेदार कम्पनी को रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, लेकिन काम फ़िर भी ज्यों का त्यों ही है।

इस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत राज्य सरकार का थर्मल पावर हाउस रहा है जो व्यापक विभागीय भ्रष्टाचार के चलते अपनी मौत खुद ही मर गया। लेकिन इसके अलावा राज्य भर में तथा दिल्ली में मौजूद ऐसे ही थर्मल प्लांट भी तो वही कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे होने वाले प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता। इसे रोकने के लिये करोड़ों रुपये के इलेक्ट्रोड प्रेसिपिटेटर लगाने का दावा तो किया जाता है परन्तु भ्रष्टाचार के चलते वे लगते जरूर हैं परन्तु काम नहीं करते। गैस आधारित अनेकों थर्मल प्लांट केवल इसलिये बन्द खड़े है क्योंकि कांग्रेस और मोदी का लाडला मुकेश अम्बानी देश भर की प्राकृतिक गैस पर कुंडली मारे बैठा है। इसकी वजह से करीब 40 हज़ार मेगावट बिजली का उत्पादन रुका पड़ा है। बिजली उपलब्ध न होने के कारण घर-घर और दुकान-दुकान पर जनरेटर न केवल धुंआं उगलते हैं बल्कि कानफ़ोड़ू शोर भी करते हैं। दिल्ली के सदर बाज़ार जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तो उनके चलते दम घुटने लगता है।

ग्रीन ट्रब्यूनल के जज स्वतंत्र कुमार को यह सब तो दिखाई नहीं देता उन्हें दिखाई देते हैं सड़कों पर चलते वाहन। कभी ट्रकों की दिल्ली एन्ट्री बन्द कर दो तो कभी 15 साल पुरानी तो कभी 10 साल पुराने वाहनों को बन्द कर दो। एन सी आर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में विधिवत योजनानुसार बन चुके फ्लैटों को प्रदूषण के लिये दोषी ठहराया जाता है। ऐसी ही दुकानदारी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कुलदीप सिंह भी चला कर जा चुके हैं। इन्होंने पहले सूरजकुंड के 16 किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य रोके थे। 'फ़ीस' मिलने के बाद इस सीमा को घटा कर धीरे-धीरे एक किलोमीटर कर दिया था। इस अरावली में आरक्षित वन क्षेत्र में धड़ाधड़ अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं तो केवल रिश्वत के बल पर।

प्रदूषण का एक अन्य बड़ा स्रोत सीवरेज व्यवस्था है। जगह-जगह उफ़नते सीवरों से गंदगी बहकर, सड़कों पर फ़ैल रही है। अनेकों जगह छोटे-बड़े गड्ढे गंदगी भरे छोटे तालाबों का रूप लिये खड़े हैं। अकेले फ़रीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के तहत करोड़ों रुपये सीवेज निकासी व ट्रीटमेंट प्लांटों पर भ्रष्टाचारियों के पेट में समा चुके हैं। इसके चलते ट्रीटमेंट प्लांट बेकार खड़े हैं और गंदगी ज्यों की त्यों गुड़गांव व आगरा नहर तथा यमुना में पहुंच रही है। दिल्ली व गाज़ियाबाद का हाल भी कोई बेहतर नहीं है। इनका भी सारा सीवेज वेस्ट यमुना व हिन्डन में बहा दिया जाता है।

सरकारों में व्यापक भ्रष्टाचार व हरामखोरी के चलते न तो पूरे एन सी आर में वांच्छित पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है और न ही बाईपास की। जो के एम पी (कुंडली मानेसर पलवल) बाइपास 20 बरस पहले चालू हो जाना चाहिये था अभी तक अधर में है तो केवल भ्रष्टाचार व सरकारी हरामख़ोरी के चलते। दूसरा पूर्वी बाइपास जो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर आदि से होते हुए पलवल तक आना था वह अभी सरकारी फ़ाइलों में ही कैद है। यदि समय रहते ये चालू हो जाते तो दिल्ली व फ़रीदाबाद को उन लाखों वाहनों की भीड़ से बचाया जा सकता था जिनको इधर या उधर आने-जाने के लिये इन शहरों से गुज़रना पड़ता है। इससे करोड़ों रुपये का आयातित तेल का धुंआ तो पर्यावरण में घुलता ही है, आम आदमी का समय व पैसा भी बर्बाद होता है। हां पर्यावरण के नाम पर तुग़लकी फ़र्मान जरूर जारी किये जा सकते हैं। कभी वाहनों की एन्ट्री पर रोक लगा दो, कभी पुराने वाहनों को जब्त करा दो।

प्रदूषण नियन्त्रण के नाम पर बीसियों बरस से एक और दुकानदारी चल रही है 'घूमा पर्ची' यानी वाहनों की प्रदूषण जांच की एक पर्ची। यह भी अपने आप में किसी घोटाले से कम नहीं। रिश्वत व अन्य जुगाड़बाज़ी से कुछ जुगाड़ी लोग सरकार से वाहनों के प्रदूषण जांच का पट्टा लेकर एक फ़र्जी सी मशीन रख कर बैठ जाते हैं तथा बिना किसी जांच के वाहनों से जांच फ़ीस लेकर पर्चियां काटते रहते हैं। करीब 10 वर्ष पूर्व जब इस तरह के कई बड़े घोटाले उजागर हुए तो पता चला कि वाहन तो जांच मशीनों के पास तक भी नहीं जाते बल्कि पर्चियां कट कर स्वयं उन तक पहुंचा दी जाती हैं। उसके बाद से कम्प्यूटराइज फ़ोटो की व्यवस्था की गयी, परन्तु फ़र्जीवाड़ा फ़िर भी नहीं रूका।

यातायात कुप्रबन्धन के चलते लगने वाले जाम तथा खस्ताहाल खड्डेदार सड़कों के चलते ज़्यादा तेल धुंआ बनकर हवा में घुलता है। पेट्रोल व डीज़ल में मिट्टी तेल आदि की मिलावट से जहां वाहनों के इंजनों का सत्यानाश होता है वहीं प्रदूषण भी बढता है। और इन सबके पीछे एक ही बात है भ्रष्टाचार, जिसने इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया उसे गोली मार दी जाती है या जिंदा जला दिया जाता है।

इस भ्रष्ट व्यवस्था का पोषण करने वाली सरकारें पर्यावरण के नाम पर व्यवसाय एवं नौटंकी तो कर सकती है परन्तु प्रदूषण को दूर नहीं कर सकती।

ख़बर दार

मै ठान लूं तो अपनी भी नहीं सुनता-अनिल विज

खट्टर सरकार में एकमात्र ईमानदार माने जाने वाले मन्त्री अनिल विज को प्रायः छटपटाते देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अस्पतालों पर छापे मारते तथा अपने क्षेत्र में दूसरे विभागों के भ्रष्टाचार पर भी आवाज उठाते वे अक्सर नज़र आते हैं। आई ए एस अधिकारी अशोक खेमका को जब परिवहन विभाग से बदला गया तो विज ने मामला मुख्यमंत्री से उठाने की बात कही थी। इस संदर्भ में 'मज़दूर मोर्चा' ने विज से एक काल्पनिक साक्षात्कार किया है।

म.मो.– खेमका के अचानक तबादले पर आपका क्या कहना है?

विज– मैं शुरू से खेमका को ईमानदार अफ़सर मानता हूं। मैं इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाऊंगा।

म.मो.–यह बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। पर हुआ तो कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया है कि प्रशासनिक रूप से किसे कहां रखना है यह सरकार तय करती है।

विज–मुख्यमंत्री जी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन मैं उनसे यह पूछूंगा कि खेमका को पहले भी (साढे चार महीने पहले) ठीक समझकर ही परिवहन विभाग में लगाया था। तो भला अब क्या हो गया?

म.मो.–आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पास आपके इस सवाल का जवाब होगा?

विज–उनके पास जवाब है या नहीं यह तो वही जानें पर मैं सावल तो जरूर पूछूंगा। मैं एक बार ठान लूं तो अपनी भी नहीं सुनता।

म.मो.– कहा जा रहा है कि खेमका को बदलवाने में आपके मन्त्रिमंडल के सहयोगी रामविलास शर्मा का पूरा-पूरा हाथ है। क्या आप शर्मा के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट लॉबी के इशारे पर चल रहे हैं?

विज–यदि जरूरत पड़ी तो मैं यह भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। पर जैसा मैने कहा मुझे पहले मुख्यमंत्री से बात करनी है।

म.मो.–मुख्यमंत्री से आपको बात करने में इतनी देर क्यों लग रही है?

विज–अन्य विषयों पर तो बात हो रही है पर इस विषय के लिये मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। जैसे ही समय मिलेगा बात हो जायेगी।

म.मो.–कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के पास खेमका को बदलने के निर्देश झंडेवालान/आलाकमान से आये हों। ऐसे में आपकी बात का उन पर क्या असर पड़ेगा?

विज–यह समस्या तो है। बहुत दिनों से बाबा रामदेव ने भी भ्रष्टाचार व कालेधन पर बोलना बंद कर रखा है। देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं यही कह सकता हूं कि एक बार ठान लूं तो फ़िर अपनी भी नहीं सुनता।

अनिल विज **राम बिलास**

सहयोगी या भुगतभोगी

खेमका ने मुख्यमंत्री को दी सफ़ाई लेकिन नहीं हुई भरपाई

चंडीगढ (म.मो.) वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी अशोक खेमका की ईमानदारी एवं कर्त्तव्य-निष्ठा से तंग आकर भाजपाई खट्टर सरकार ने उन्हें परिवहन जैसे भ्रष्टतम विभाग से उठाकर संग्रहालय में रख छोड़ा है। इससे पहले की कांग्रेसी व अन्य सरकारें जब खेमका के साथ ऐसा ही करती थीं तो भाजपा नेता बड़ी उछल-कूद मचाते तथा खेमका के गुणगान करते हुए उन सरकारों की कड़ी आलोचना करते थे। परन्तु जब राज करने की अपनी बारी आई तो खेमका के साथ वही सब ये भी कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें करती रही हैं।

खेमका जैसे अफ़सरों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि सरकार चाहे चौटालों की हो या कांग्रेसियों की अथवा भाजपाइयों की, उद्देश्य सबका लूट और केवल लूट ही रहता है। परिवहन विभाग में तैनाती के समय खेमका साहब बेशक अपने मन में इस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करके सुचारू रूप से चलाने की सोच रहे हों; लेकिन खट्टर ने उन्हें इस काम के लिये नहीं बल्कि इस विभाग के महाभ्रष्ट मंत्री रामबिलास की नकेल कसने के लिये लगाया था। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 'मज़दूर मोर्चा' में खेमका की तैनाती के समय ही प्रकाशित कर दी गयी थी।

रामबिलास की एक तारीफ़ सर्वविदित है कि वह लूट के माल को अकेला न हड़प कर आला कमान के उन सब लोगों में भी बांटता है जिनके पल्ले कुछ होता है। इसी की बदौलत रामबिलास अपनी इस नकेल को निकलवा कर संग्रहालय में रखवा पाये हैं। अब वे पूरी मनमानी एवं बेरोक-टोक इस महकमे को खुला चर सकेंगे, जिसका लाभ आला कमान तक भी बराबर पहुंचेगा ही।

एक अन्य आई ए एस अधिकारी प्रदीप कासनी की ही तरह खेमका को भी शायद इस तरह की ओछी सियासी पैंतरेबाज़ी की समझ नहीं रही होगी। इसीलिये वे मुख्यमंत्री को अपनी सफ़ाइयां देते घूम रहे हैं। सफ़ाई उन्हें दी जाती है जिन्हें तथ्यों की जानकारी न हो, यहां तो सारा खेल ही प्रायोजित है।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज़ जरूर एक-दो बार खेमका के हक में बोलते दिखे, परन्तु अब वे भी टांय-टांय फ़िस नज़र आते हैं। यदि उनके पल्ले कुछ होता है तो वे खेमका को कम से कम अपने महकमे में तो ले ही सकते थे जबकि 31 मार्च को ही आर पी चन्दर के रिटायर होने से एक पद खाली हुआ था। उसका कार्यभार भी अतिरिक्त रूप से उन्ही रामनिवास को दे दिया गया है जो विज की कतई परवाह नहीं करते।